

समय सीमा समीक्षा बैठक दिनांक 06.08.2018 का कार्यवाही विवरण।

आज दिनांक 06.08.2018 को समय सीमा बैठक श्रीमति छवि भारद्वाज, कलेक्टर जबलपुर की अध्यक्षता में आयोजित हुई, जिसमें मुख्यकार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, अपर कलेक्टर एवं नगरीय एस.डी.एम. तथा विभाग जिला प्रमुख उपस्थित रहे।

1. **समाधान आनलाईन :-** आगामी समाधान आनलाईन के चयनित विषय एवं संबंधित विभागवार समीक्षा की गई :-

1. **खाद्य विभाग-** पात्रता पर्ची न मिलने संबंधी। जिसमें 16 शिकायतें लंबित है। एक सप्ताह में पात्रता पर्ची जारी करने के पूर्व निर्देश के बावजूद यथास्थिति है।
2. **गृह विभाग-** आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी न करना/पक्षकारों पर समझौते, राजीनामा के लिये दबाव डालने संबंधी। जिसमें 02 शिकायतें लंबित है।
3. **कृषि विभाग -** मुख्यमंत्री योजनाओं के लाभ न मिलने संबंधी। पूर्व निर्देश के बावजूद अभी भी 20 शिकायतें लंबित है।
4. **ऊर्जा विभाग -** फ्लेट रेट/किसान संबंधी/दीनबंधु आदि योजना अंतर्गत लाभ न मिलने संबंधी। जिसमें 4 शिकायतें लंबित है।
5. **नगरीय विकास एवं आवास -** घरों/निचली जगहों/बेसमेंट/नाली आदि में वारिस पानी भर जाने संबंधी। अब शिकायतें लंबित नहीं हैं।
6. **आदिमजाति विभाग -** महाविद्यालयीन कक्षाओं हेतु आवास भत्ता प्राप्त न होना/विलंब से होना/निर्धारित दर से प्राप्त न होना संबंधी। जिसमें 04 शिकायतें लंबित है। 2016-17 के आवास गृह एवं स्कालर शिप के प्रकरण एक या दो साल पुराने हो चुके हैं। स्वयं परीक्षण कर निराकरण के बार-बार निर्देश के बावजूद शिकायतों का निराकरण नहीं किया जाना अत्यंत आपत्ती जनक है। तत्कालीन प्रभारी सहायक आयुक्त के विरुद्ध निलंबन की कार्यवाही की गई।
7. **सभी विभाग -** 300 दिन से ज्यादा लंबित। जिसमें जिले की कुल 214 शिकायतें लंबित है। जिसमें कृषि विभाग के अंतर्गत कृषि विकास की 32, फसल बीमा की 32, वन विभाग की 35, पंचायत विभाग की 16, वित्त विभाग लीड बैंक की 16, एन.एच.ए.आई. की 18, चिकित्सा शिक्षा की 17, अनुसूचित जाति/जनजाति की 13, डी.ई.ओ. की 09, डी.पी.सी. की 3, संस्कृति विभाग की 6, सामाजिक न्याय की 4, नगर निगम की 3, पशुपालन की 5, राजस्व विभाग की 2, तकनीकी शिक्षा की 02, कौशल विकास की 03 शिकायतें लंबित पाई गई।

दुखद है कि पिछले तीन माह से लगातार हिदायतों के बाद व गहन समीक्षा के पश्चात भी अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं। फलस्वरूप एक जिला अधिकारी प्रभारी ए.सी.टी.डब्ल्यू के विरुद्ध निलंबन की कार्यवाही की गई है। लिपकीय लापरवाही के लिए जिला अधिकारी

जिम्मेदार है, फिर से चेतावनी दी गई कि विभागीय लंबित शिकायतों पर व्यक्तिगत ध्यान देकर निराकरण करने के कड़े निर्देश दिए गए।

2. सी.एम.हेल्प लाईन :- कलेक्टर महोदया द्वारा सी.एम.हेल्प लाइन की विस्तृत समीक्षा की गई। पोर्टल पर प्रदर्शित सूची अनुसार जबलपुर जिले के अधिकांश विभागों के एल-1 एवं एल-2 स्तर के अधिकारियों का परफॉर्मंस इस बार भी निम्नतर पाया गया। पूर्व बैठक में कलेक्टर महोदया द्वारा गहरी नाराजगी व्यक्त की गई थी। समय सीमा बैठकों में लगातार समीक्षा व निर्देश तथा नोटिस जारी किये जाने के बावजूद संबंधित अधिकारियों द्वारा बिलकुल भी गंभीरता नहीं दिखायी गयी और न ही समुचित कार्यवाही की जा रही है।

एक- सबसे अधिक पुरानी 100 दिन से अधिक की शिकायतें - जिसमें प्रत्येक विभाग की एक-एक शिकायत की सूची अनुसार समीक्षा की गयी। जिला अधिकारी से लंबित रहने का कारण पूछा गया। आदिम जाति कल्याण विभाग, वन विभाग, कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग, स्कूल शिक्षा, संस्कृति विभाग, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग, पशुपालन एवं डेयरी विभाग, किसान कल्याण एवं कृषि विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, तकनीकी शिक्षा कौशल विकास एवं रोजगार विभाग, सामाजिक न्याय एवं निःशक्त जन कल्याण विभाग, राजस्व विभाग, जन शिकायत निवारण विभाग, खेल एवं युवा कल्याण विभाग, उर्जा विभाग, सहकारिता विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, नर्मदा घाटी विकास विभाग, नवकरणीय उर्जा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, शामिल हैं।

राजस्व विभाग 100 दिवस से अधिक की लंबित शिकायतों के प्रकरण आज शाम निकालकर बतायें। शिकायत क्रमांक. 4252344 न्यायालय नायब तहसीलदार नजूल जबलपुर व 4563706 इसे नोट करें। ए.सी.टी.डब्ल्यू, वन विभाग, संस्कृति, कुटीर उद्योग, स्कूल शिक्षा, तकनीकी शिक्षा केस निकालकर दिखाइये। सहकारिता केस नं. 4671935 निकालें पालन नहीं करा पा रहे हैं।

एल-1 स्तर पर — (सफलता पूर्वक निराकरण 01.07.18 से 31.07.18 तक की स्थिति जिनका 0 प्रतिशत निराकरण है)- 0 प्रतिशत निराकरण में राजस्व विभाग-श्याम सुंदर आनंद नायब तहसीलदार, स्मार्ट सिटी-नगर निगम- रवि राव प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस विभाग- 06

अधिकारी, अभिलेख शाखा—स्कूल शिक्षा— श्रीमति प्रभा मिश्रा प्राचार्य, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण—विनाही दहात प्रबंधक, फसल बीमा—सहकारिता— अलोक यादव महाप्रबंधक केंद्रीय सहकारी बैंक, गृह निर्माण मंडल— शैलेन्द्र शुक्ला सहायक यंत्री, लोक स्वास्थ्य— डॉ. शत्रुघन दाहिया विकासखंड चिकित्सा अधिकारी, प्रधानमंत्री आवास योजना—ग्रामीण— मनीष शेंडे मुख्य कार्यपालन अधिकारी, सीमांकन—संदीप जायसवाल तहसीलदार पाटन, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना— विनीत कुमार श्रीवास्तव महाप्रबंधक, लोक स्वास्थ्य—सोनू शर्मा विकासखंड चिकित्सा अधिकारी हैं।

एल-1 स्तर पर — (संतुष्टि के साथ निराकरण 01.07.18 से 31.07.18 तक की स्थिति तक की स्थिति जिनका 0 प्रतिशत निराकरण है)— 0 प्रतिशत निराकरण खाद्य आपूर्ति विभाग— पी. एल.राय ए.एस.ओ., कृषि विभाग— भरत प्रसाद दुबे मंडी सचिव व डी.के. श्रीवास्तव वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, खेल एवं युवा कल्याण— राजेश मनोध्या जिला खेल अधिकारी, उर्जा विभाग—05 अधिकारी, जन शिकायत निवारण— व्ही. के. कर्ण डिप्टी कलेक्टर, जनसंपर्क विभाग— आनंद जैन, तकनीकी शिक्षा— उमाशंकर द्विवेदी प्रशिक्षक, पंचायत— विनीत कुमार श्रीवास्तव जी. एम., जी.पी.कोरी ई.ई. आर.ई.एस., व्ही.सी.श्रीवास्तव ई.ई., पशुपालन— डॉ. आर.के. कुर्मी, महिला एवं बाल विकास— प्रशांत पुराबिया एवं सुमन तिवारी सी.डी.पी.ओ., योजना— यशवंत वैद्य, सी.एल. पनिका माधुरी शर्मा, राजस्व विभाग—श्याम सुंदर आनंद ना.तह., लोकमन कोरी ना.तह., कुटीर एवं ग्रामोद्योग— अशोक पखाले कनिष्ठ सहायक ग्रामोद्योग विस्तार., आयुष विभाग— डॉ. रविकांत श्रीवास्तव प्रधानाचार्य व डॉ. अर्चना मरावी जिला आयुष अधिकारी, उच्च शिक्षा—03, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण— राकेश कुमार चतुर्वेदी व गनेश सिंह मरकाम एस.एच.डी.ओ., लोक निर्माण विभाग— व्ही.एन. शुक्ल, योगेश कुमार वत्सल, राजेश कुमार मिश्रा (सभी एस.डी.ओ.) , लोक सेवा प्रबंधन— शुभांगी शुक्ला जिला प्रबंधक, लोक स्वास्थ्य — डॉ. सोनू शर्मा, डॉ. शत्रुघन दाहिया, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी— डी.एस.जवाहर, जे.के. जैन सहायक यंत्री, वन विभाग— जगदीश प्रसाद वास्पे, त्रिवेणी बरकड़े, अभय कुमार पांडे, वाणिज्य कर— आभा जैन, वित्त विभाग— अमित विजय पाठक संयुक्त संचालक, आर.के. मिश्रा संभागीय पेंशन अधिकारी, विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जाति कल्याण— आशीष दीक्षित सहायक संचालक, श्रम विभाग— ए. पी. सिंह उपसंचालक, स्कूल शिक्षा— प्रभा मिश्रा प्राचार्या, नीरजा गोरे, सी.एल.बागरी बी.आर.सी., पी.एल.

रैदास, बी.आर.सी. सिहोरा, सूचना एवं प्राद्योगिकि— अभिषेक बकोड़े सहायक प्रबंधक ई—गर्वनेंस, सहकारिता— आलोक यादव महाप्रबंधक केन्द्रीय सहकारी बैंक, सामाजिक न्याय— बाला प्रसाद गुप्ता सी.एम.ओ. सिहोरा, किशोर सिंह राजपूत सी.एम.ओ. शहरीब का।सर सी.एम.ओ. मंझौली, जे. पी.सेन सी.एम.ओ. पनागर, उर्जा विभाग— कुंदन कुमार कनि.अभि. , आर.सी. तिवारी कनि. अभि., अमित सक्सेना सहायक अभि., हरीश गुप्ता सहा. अभि., सुजीत खटीक उप निदेशक, सुधा मिश्रा कार्य अभि., एस. व्ही. वजे. कार्य अभि., गृह विभाग— इंद्रमणि पटेल, सुशील चौहान अनिल गुप्ता हैं।

दो— ओवर ऑल सेटिस्फेक्शन—(01.07.18 से 31.07.18 तक की स्थिति तक की स्थिति जिनका 0 से 40 प्रतिशत निराकरण वाले विभाग)— सहकारिता, परिवहन, वन, पशुपालन, राजस्व, सामान्य प्रशासन, स्कूल शिक्षा, गृह, पंचायत, लोक स्वास्थ्य, उच्च शिक्षा, आदिम जाति, कृषि, सूचना, नर्मदा घाटी, खाद्य, जल संसाधन, विधि, वित्त, लोक निर्माण एवं आयुष विभाग हैं। ये वही विभाग हैं जिनका परफारमेंस लगातार खराब है। आयुष विभाग का निराकरण 0 प्रतिशत होने पर गहरी नाराजगी व्यक्त की गई।

तीन— टॉप 5 डिफाल्टर (01.07.18 से 31.07.18 तक की स्थिति):— एल-1 अधिकारी— लोक स्वास्थ्य— डॉ. सोनू शर्मा, राजस्व विभाग— श्याम सुंदर आनंद, पुलिस विभाग— इंद्रमणि पटेल व सुशील चौहान, स्मार्ट सिटी— नगर निगम— रवि राव, (सभी 0 प्रतिशत),

उपरोक्त सभी एल-1 अधिकारी जिनका 0 प्रतिशत निराकरण है उन्हें संबंधित विभाग की ओर से नोटिस जारी किया जाए एवं ऐसे अधिकारी जिनका परफारमेंस बार-बार 0 प्रतिशत है। उनके विरुद्ध दो वेतन वृद्धि रोकने की कार्यवाही हेतु नियत उच्च अधिकारी को प्रस्ताव भेजे जाएं तथा की गई कार्यवाही नस्ती पर कलेक्टर को प्रस्तुत की जावे।

चार— टॉप 5 परफॉर्मर (01.07.18 से 31.07.18 तक की स्थिति) :- एल-1 अधिकारी— खनिज साधन विभाग— देवेन्द्र पटेल, लोक स्वास्थ्य— डॉ. सी.के.अतरोलिया, पिछड़ा वर्ग व अल्पसंख्यक कल्याण विभाग— आशीष दीक्षित, श्रम आयुक्त कार्यालय— जे.एस. उद्दे, व प्रकाश व्यवस्था नगर निगम— नवीन कुमार लोनारे को उनके अच्छे परफॉर्मंस पर प्रशास्ति पत्र देने के निर्देश लोक सेवा प्रबंधन को दिये गये।

3. **निर्वाचन :-** अपने- अपने जोन के मतदान केन्द्रों का निरीक्षण जोनल अधिकारी को देखना है। मतदाता सूची को बूथ लेवल पर चेक करना है। उसमें कितने नाम जोड़े गए हैं कितने हटाए गए हैं के अनुसार शुद्धिकरण किया जाना। मतदाता सूची में कोई भी 18 साल या अधिक के नये वोटर नहीं छूटना चाहिए। 100 साल से अधिक का मतदाता पृथक से चिन्हित होना चाहिए। 01.01.2000 को जन्म लिए मिलेनियम वोटर को इस साल ब्रांड एम्बेसेडर बनाया गया है। उन्हें चिन्हित कर लिया जाए। इसके लिए चैकलिस्ट तैयार की जाए। विधान सभा वार किसे जोनल अधिकारी होंगे। सभी अधिकारियों से जोनवार 15 दिवस बाद बैठक ली जाएगी। पिछली बार के पोल बायकॉट को चिन्हित करना व फीड बैक लेना आवश्यक है। मतदान दिवस पर मामला बनता है। नाम सूची में न होने पर विवाद की स्थिति बनती है जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए विस्तृत रूप से मतदाता सूची को देखना सबसे महत्वपूर्ण है। सभी कर्मचारी/अधिकारियों का शत-प्रतिशत डेटाबेस पूर्ण रहना चाहिए। सभी विभाग को निर्देश दिए गए कि आगामी टी एल में विधान सभा वार जोनल अधिकारियों से चर्चा की जाएगी। जोनल अधिकारी 50-60 लोगों को एकत्र कर बी.एल.ओ. के साथ ग्राम में जाएं। जिम्मेदारी जोनल अधिकारी की होगी। स्वयं मतदान केन्द्र पर विजिट कर तथा अपने सभी मतदान केन्द्र पर जाएं। सभी जोनल अधिकारियों को कम्प्यूनिकेट संबंधित विभाग अधिकारी करें।

भविष्य में संभावित परेशानी को अभी से निपटाया जाना चाहिए। यह जोनल अधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी। 15-20 मिनट प्रत्येक टी.एल. में रेण्डम चैक किया जाएगा। बी.एल.ओ. ने डोर टू डोर सर्वे किया है या नहीं उनका परीक्षण सुनिश्चित किया जाए।

सभी अधिकारी 100 प्रतिशत एम्प्लाइज डाटाबेस एक सप्ताह में पूर्ण कर लें। कोई भी विभाग विलंब न करे। 15 अगस्त तक पूर्ण कर लें। अद्यतन स्थिति में पदस्थ लोगों की जानकारी फीड हो जाए। टॉप 10 मतदान केन्द्र जहां सर्वाधिक नाम बढ़े या घटे हैं- वो असामान्य दिखाई दे रहा है। जोनल अधिकारी मतदान केन्द्र पर जाकर वस्तु स्थिति देखें। सत्यापन जोनल अधिकारी को करना है।

8. **स्वरोजगार योजना :-** हितग्राही मूलक योजनाओं की विभागवार पुनः समीक्षा की गयी। जिला उद्योग, खादी एवं ग्रामोद्योग, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक, आदिवासी वित्त एवं विकास निगम, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्यादित, जिला शहरी विकास अभिकरण, हाथकरघा, माटीकला बोर्ड, विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति कल्याण विभाग, किसान कल्याण तथा कृषि विभाग, उद्यानिकि तथा खाद्य प्रसंस्करण मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास, पशुपालन विभाग हैं। उक्त विभागवार समीक्षा की गई। लक्ष्य के विरुद्ध प्रगति अत्यंत कम है।

अब से वितरण की स्थिति पर ही मॉनीटरिंग की जाएगी। सभी विभाग ध्यान दें।
वितरण 60 से 70 प्रतिशत तक अगस्त के अंत तक हो जाए।

4. निर्माण विभाग :- खनिज विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि बड़ी मात्रा में रेत का भंडार है। निर्माण से संबंधित सभी विभाग आवश्यकतानुसार डिमांड बनाकर खनिज विभाग से संपर्क करें। आज शाम तक भेजें ताकि आबंटन किया जा सके। रायल्टी के आधार पर पेमेंट किया जाना है।
5. नये पटवारियों का वेतन. :- जिले में नये 160 पटवारी प्रशिक्षण हेतु आ रहे हैं। उनके वेतन की तैयारी हेतु निर्देश टी.ओ. को दिये गये।
9. टी.एल. प्रश्न :- समय सीमा के प्रश्नों की विभागवार समीक्षा अगली टी.एल. में की जाएगी। पूर्व में निर्देश दिए गए कि ऐसी शिकायतों पर गंभीरता दिखाई जाकर समय सीमा 07 दिवस में निराकरण किया जाये। टी.एल. प्रश्न में व्यक्तिगत रुचि लेकर प्राथमिकता के आधार पर जिला अधिकारी निराकरण कराएं।

समय सीमा के प्रश्नों का निराकरण होने पर सर्वसंबंधित अधिकारी कलेक्टर के समक्ष नस्ती/प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। उक्त निर्देशों के साथ मीटिंग सधन्यवाद समाप्त की गई।

कलेक्टर,
जबलपुर

पृ.क्र/ 5876 /अधीक्षक/टी.एल/2018

जबलपुर दिनांक 08 अगस्त 2018.

प्रतिलिपि :-

1. कमिश्नर जबलपुर संभाग जबलपुर।
2. जिले के समस्त विभाग प्रमुख को सूचनार्थ पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

कलेक्टर,
जबलपुर